मध्य प्रदेश में आर्थिक महत्व की सड़कों/पुलों का निर्माण

411. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़कों/पुलों की आर्थिक महत्ता का निर्धारण करने के लिए क्या-क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में आर्थिक महत्व की अन्तर-राज्यीय सड़कों/पुलों के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी;

(ग) उन नये पुलों की जिले-वार संख्या कितनी है जिनका निर्माण कार्य गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सहायता से शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) सड़कों/पुलों के आर्थिक महत्व के निर्धारण से संबंधित मापदंड नीचे दर्शाए गए हैं:—

(I) नए क्षेत्र खोलने के लिए अपेक्षित सड़कें/पुल, जहां निकट भविष्य में रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती;

(II) ऐसी सड़कें/पुल जो तेज आर्थिक विकास में काफी सहायक हों, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में जहां पर्याप्त खनिज पदार्थ दोहन के लिए उपलब्ध हों।

(ख) से (ङ) जी नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सैक्टर की सड़कों के कार्यक्रम के लिए सीमित निधियां आवंटित होने के कारण इस कार्यक्रम के तहत कुछेक चुनिंदा परियोजनाओं पर ही कार्य कर पाना संभव होगा।

केन्द्रीय सड़क निधि से भुगतान की गई धनराशि

412. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 1982 में दुधी-विक्रमगंज रोड पर कन्हर ब्रिज का अनुमोदन होने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत अब तक वर्ष-वार दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान उपर्युक्त मद के अंतर्गत कितनी धनराशि की मांग की है;

(ग) क्या इस धनराशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) निधियों का आबंटन स्कीम-वार नहीं बल्कि राज्य-वार किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1993-94 में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्य के लिए अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, पहले जारी की गई कुल निधियों, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता, राज्यों द्वारा परियोजित अपेक्षाओं और बजट प्रावधान संबंधी समग्र उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए 2.50 करोड़ रु० की आवश्यकता की तुलना में 1.00 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं।

Declaration of National Highways in Gujarat

413. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the State Government of Gujarat has forwarded proposals to the Central Government for declaring new National Highways in the State;

(b) if so, whether the proposals of various roads to be declared as National Highways in the State have been examined by the Central Government;

(c) whether during the Seventh Five Year Plan period no new National Highways were consented in the State of Gujarat;

(d) whether the Central Government have decided to declare some of the roads as National Highways in the State; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH